THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India's policy encourages the setting up of captive power plants after such plants obtain the cocnerned State Electricity Board's permission.

(c) and (e) Under section 44 of Electricity (Supply) Act 1948, the State Electricity Board is required to consult Central Electricity Authority before giving their consent for setting up of captive power plants in case where the additional or new generating capacity exceeds 25MW. while for capacities below this limit the concerned State Electricity Board has the power to give approval.

(e) and (f) The progress and performance of captive power plants is not being monitored by Government of India.

विद्युत पारेषण के लिये परियोजनाएं तैयार किया जाना

568. **श्री राम जेठमलानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिजली के पारेषण हेतु कुछ परियोजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कौन-कौन सी है तथा इनकी अनुमानित निर्माण लागत क्या-क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं में विदेशी पूंजी निवेश की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये गत कुछ महीनों के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडलों को विदेशों में भी भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो ये प्रतिनिधिमंडल कब-कब विदेशों में गए थे तथा इनके सदस्य कौन-कौन थे; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि अभी भी कानूनन विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु छूट नहीं दी जा सकी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) जी, हां।

(ख) 9वीं योजना के दौरान पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख पारेषण परियोजनाएं निम्नवत हैं।

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
टिहरी पारेषण प्रणाली	484
तलचेर पारेषण प्रणाली	2600
सांसाराम एचवीडीसी बी / बी प्रोजेक्ट	568
एनईआरएलडीसी	159
ईआरएलडीसी	588
डब्ल्यू आर एलडीसी	588
धोलीगंगा पारेषण प्रणाली	317
रायपुर-राऊरकेला पारेषण प्रणाली	195

पावरग्रिड कारपोरेशन ने निजी भागेदारी के लिए निम्नलिखित छः परियोजनाओं को भी अभिज्ञात किया है।

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र के बीच एक ए सी इन्टर कनेक्टर	300
सीईपीए० पारेषण (उ०क्षे० के लिए)	3355
सीईपीए पारेषण (प०क्षे० के लिए)	1300
चिकननैक में पारेषण प्रणाली	350
एचवीडीसी तलचेर पारेषण प्रणाली	1250
एचवीडीसी टर्मिनल तालचेर-II	1520

(ग) मंत्रीमंडलीय सचिव के नेतृत्व में एक संयुक्त सरकारी / व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने देश में विद्युत क्षेत्र समेत अवसंरचनात्मक ढांचे में निवेश करने के लिए निर्णयों को सम्भवतः अधिक प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार की अभिरुचियों के संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने तथा मिलने के लिये सं० राष्ट्र अमेरिका का दौरा किया है। प्रतिनिधिमंडल ने निवेशों से संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापार और वित्त व्यवस्था में लगे हुए

कई सारे लोगों और मुख्य सरकारी विभागों के व्यक्तियों तथा बहुपक्षीय एजेंसियों से भी मुलाकात की है।

(घ) मंत्रीमंडलीय / सचिव के नेतृत्व में संयुक्त सरकारी / व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने जून 1997 में 7 कार्य दिवसों (8 से 18 जून 1997 के बीच) सं० राज्य अमेरिका का दौरा किया था। सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम निम्नवत है:—

1. श्री टी० एस० आर० सुब्रमणियन, मंत्रीमंडलीय सचिव
2. श्री एन पी० बागची सचिव कोयला मंत्री
3. श्री योगेन्द्र नारायण, सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय
4. डा० शंकर एन आचार्य मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय।
5. श्री श्याम लाल घोष, सचिव इलैक्ट्रानिक विभाग (केवल सैन जोस)
6. श्री प्रदीप बैजल, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय
7. डॉ अविनाश चन्द्र, महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
8. श्री धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिवालय।

व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम निम्नवत है।

1. श्री अनिल अमानी, प्रबंधक निदेशक, रिलायन्स इंडेस्ट्री
2. श्री के० के० मोली, अध्यक्ष, मोदी इंटरप्राइजेज
3. श्री के० जी० रामानाथन, सीएमडी आई०पी०सी०एल बड़ौदा
4. श्री अशोक अग्रवाल, निदेशक टीसीआई इन्फ्राइन्ट्रक्सन फाइनेस लि०
5. श्री सी० दास गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक, सीईएससी लि०
6. डा० सोम दत्त, सोमदत्त बिल्डर्स
7. श्री सी० एल० वर्मा, सीएमडी, कौन्टीनेन्टल कन्ट्रक्सन लि०
8. श्री के० एन० शिनाय, कार्यकारी अध्यक्ष, एबी बी लि०
9. श्री आर० सेशासायी, उप प्रबंध अशोक लिलैण्ड लि०
10. श्री ए० रामाकृष्णा, अध्यक्ष (प्रचालन) लारसन एण्ड टबरो।
11. डॉ अशोक हारने, मुख्य कार्यकारी, पावर बिजनिस ग्रुप आईएलएफएस
12. श्री एस चन्द्रशेखर, प्रबंध निदेशक, भूस्का पावर कारपोरेशन लि०

(ङ) निजी विद्युत नीति भारत के विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अपनी पूंजी निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है।

विद्युत की तुलनात्मक कीमतें

569. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बतोन की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1997 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में "ऑफ पावर रिफार्म्स एण्ड काम्पिटीशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाय गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अमरीका और ब्रिटन में आई० पी० पी० बिजली की कीमत 1.40 रुपये तथा 1.60 रुपये प्रति कि० वा० है जो निरंतर प्रतिस्पर्धा के कारण और कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत में ये कीमतें 2.20 से 2.50 रुपये प्रति कि० वा० तक है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निजी क्षेत्र के बिजली क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण उपरोक्त कीमतों में और भी वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य (श्री योगेन्द्रकुमार भगतराम अलघ): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी की टैरिफ का निर्धारण भारत सरकार की 30.3.92 (क्या संशोधित) की टैरिफ अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा। एक विद्युत स्टेशन की टैरिफ उसकी समापन लागत, प्रौद्योगिकी, वित्त-पोषण का तरीका, ब्याज दर, प्रकार, ईंधन का मूल्य व स्रोत, ईंधन एवं उपस्कर पर कर और शुल्क, समापन का वर्ष, बिजली की कीमत